

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I-Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 160}

नई दिल्ली, शुक्रवार, प्रगस्त 26, 1977/भाव 4, 1899

No 160]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 26, 1977/BHADRA 4, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह ग्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LAW JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

RESOLUTION

New Delhi, the 26th August 1977

No. 7/6/77-CL.V.—The Central Government hereby appoints Shri Justice Rajindar Sachar, Judge of the High Court of Delhi, as Chairman of the high powered committee constituted by the Resolution of the Government of India in the Ministry of Law, Justice & Company Affairs (Department of Company Affairs) No. 7/6/77-CL V, dated the 23rd June 1977, for undertaking a comprehensive review of the Companies Act, 1956 and the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969, in place of Shri K. S. Hegde, resigned

Order

Ordered that a copy of this Resolution also be communicated to all the State Governments, Union Territories, Ministries and Departments of the Government of India, Prime Minister's office, Cabinet Secretariat, Military Secretary to the President of India and Private Secretary to the Vice President of India

Ordered also that it be published in the Gazette of India Extra-ordinary

K K RAY, Secy

विधि, स्याय ग्रौर कस्पनी कार्य मंत्रालय (कस्पनी कार्य विभाग)

सफल्प

नई दिल्ली, 26 श्रगस्त, 1977

स 7/6/77-सी० एल० 5.—केन्द्रीय सरकार एतव्द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के न्याया-धीण, श्री न्यायाधीण, राजेन्द्र सचर को, कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा एकाधिकार एवं निबधन-कारी व्यापार प्रथा प्रधिनियम, 1969 का सर्वतोमुखी पुनर्विलोकन करने के लिए, भारत सरकार, विधि, न्याय श्रीर एवं कम्पनी कार्य मंद्रालय (कम्पनी कार्य विभाग) के दिनांक 23 जून, 1977 के सकल्प सं० 7/6/77—सी०एल० + 5 द्वारा गठित उच्च णक्ति सम्पन्न समिति के श्रध्यक्ष के पद पर श्री के० एस० हेगड़े, जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया, के स्थान पर, नियुक्त करती है।

द्यावेडा

श्रादेण दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भी सभी राज्य सरकारो, केन्द्र प्रणासित क्षेत्रों, भारत सरकार के सभी मत्नालयो व विभागो प्रधान मंत्री कार्यालय, मत्निमण्डल सचिवालय, भारत के राष्ट्रपति के सैनिक सचिव तथा भारत के उप-राष्ट्रपति के निजी सचिव को भेजी जाए।

यह भी भ्रादेश दिया जाता है कि यह भारत के श्रसाधारण राज-पद्म मे प्रकाशित की जाए। के० के० रे. सचिव।